

# डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार एवं वर्तमान दौर में उनकी प्रासंगिता

श्रीमती इन्दू आसेरी

व्याख्याता अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय आबूरोड (सिरोही) राज.

## शोध सारांश

डॉ. भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता एवं दलित नेता होने के साथ एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री भी थे। हालांकि अर्थशास्त्री के रूप में उनको बहुत ही कम लोग जानते हैं लेकिन उनके द्वारा दिये गए आर्थिक विचार उनकी उच्च कोटी की विद्वता को दर्शाने के साथ उनको महान अर्थशास्त्री के रूप में भी विशेष पहचान दिलाते हैं। उन्होंने भारतीय मुद्रा की समस्या के समाधान एवं मुल्य निर्धारण हेतु उचित स्वर्णमान मानक अपनाने की बात की तो वहीं भारत में कृषि क्षेत्र, मजदूरों, औद्योगिकरण, कराधान की समस्याओं तथा जल संसाधन नीति, महिलाओं के उत्थान आदि पर दिये गए विचार आज भी प्रासंगिक हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों एवं सिद्धांतों तथा वर्तमान दौर में इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है।

**शब्द कुंजी** - एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता, मुद्रा स्फीति, कृषि क्षेत्र।

**प्रस्तावना** - डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले के महु शहर में हुआ था। इनको सामान्यतः एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता एवं दलित नेता के रूप में जाना जाता है लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री भी थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने कहा था कि 'डॉ. भीमराव अंबेडकर मेरे अर्थशास्त्र के पिता हैं'। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की। वर्ष 1923 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से डीएससी. (अर्थशास्त्र) डीग्री प्राप्त की एवं अपने शोधप्रबंध 'दी प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस: इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन' में उन्होंने रुपये के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया। इसके अलावा वर्ष 1927 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी अर्थशास्त्र में पीएच. डी की डीग्री हासिल की। अतः ये पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएच. डी की दोहरी डीग्री हासिल की।

**डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार** : डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाए तो उनके विचारों में आर्थिक तौर से एक सुदृढ़ राष्ट्र का साफ दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन्होंने अपने जीवन में अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुखतः तीन पुस्तकें लिखी जिनमें 1- भारतीय रुपये की समस्या: उत्पत्ति एवं समाधान (Problems of Rupees Its origin and Its Solution), भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of East India Company), भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India) हैं।

**भारतीय रुपये की समस्या: उत्पत्ति एवं समाधान** : डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय रुपये की समस्या के संबंध में वर्ष 1923 में प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस : इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय मुद्रा प्रणाली की समस्याओं के बारे में वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने मुद्रा मुल्य की स्थिरता पर विशेष जोर दिया है। यह उसी प्रकार है जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति में मूल्य स्थिरता पर बल दिया जाता है। सामान्य रूप से मुद्रा स्फीति की स्थिति में अर्थशास्त्रीयों एवं नीति निर्माताओं द्वारा मुद्रा के मूल्यों को स्थिर करने पर ध्यान देने के साथ देश में

उत्पादन की मात्रा बढ़ाने हेतु त्वरित कदम उठाये जाते हैं। लेकिन डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्वर्ण मानक के संदर्भ में मुद्रा के मूल्यों को स्थिर रखे जाने पर जोर दिया है। उनके अनुसार स्वर्ण प्रतिमान वह मानक है जिसके अंतर्गत मुद्रा के मूल्य को परिवर्तित किया जाता है। इसके पिछे उन्होंने यह तर्क दिया कि सोने के विनिमय मानक में स्थिरता नहीं है एवं चुंकि इसके अंतर्गत मुद्रा की मात्रा एवं मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी की समस्या पैदा हो जाती है इसलिए भारत जैसा विकासशील देश स्वर्ण विनिमय मानकों को सहन नहीं कर सकता है।

उन्होंने आंकड़ों एवं कारकों के माध्यम से यह भी सिद्ध किया कि स्वर्ण मानक के कारण कैसे व किस तरह के भारतीय रुपये ने अपनी क्रयशक्ति खो दी है। इसके पिछे उनका सुझाव था कि सरकार द्वारा अपने घाटे को विनियमित करने के साथ धन का व्यवस्थित प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार विनिमय दर की तुलना में मुद्रा की मूल्य स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिये गए प्रतिबंधित एवं विनियमित स्वर्ण प्रतिमान के उपयोग के परिणामस्वरूप ही भारतीय रिजर्व बैंक जैसे वित्तीय सस्थाओं की स्थापना की गई जो आज भी देश की वित्तीय व्यवस्था के उचित संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय मुद्रा की समस्या के संदर्भ में स्वर्ण प्रतिमान संबंधी इनके विचार बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं।

**भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त:** डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा इस पुस्तक में वर्ष 1792 से 1858 के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं वित्त में परिवर्तन की ऐतिहासिक समीक्षा की गई है। इसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे एवं किस तरह सार्वजनिक / लोक वित्त हेतु ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किये गए। इसके अलावा उनका विचार था कि देश की सुरक्षा अर्थात् सेना आदि पर अधिक धन व्यय करना देश के व्यापक हित में नहीं है एवं इसके लिए नागरिकों से जबरन धन संग्रहित करना लोकतांत्रिक या संसदीय दृष्टिकोण से अनुचित है। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने कुल बजट का 45 से 65 प्रतिशत धन सैन्य शक्ति पर खर्च करती है एवं इसके लिए भूमि करों में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है, जबकि सोचने वाली यह है कि इंग्लैण्ड में इसी कर की राशि मात्र 10 प्रतिशत रही है। अतः उनका विचार था कि सरकार को नागरिकों से संग्रहित की गई कर की राशि को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यों पर खर्च करना चाहिए जिससे कि समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित हो सके।

**भारत में प्रांतीय वित्त का विकास :** डॉ. भीमराव अंबेडकर की यह पुस्तक उनके पीएच.डी. काल के दौरान प्रस्तुत किया गया शोध-प्रबंध है जो ब्रिटिश 1 भारत में वर्ष 1833 से 1921 तक विकास केन्द्र के संबंधों का खुलासा करता है। इस पुस्तक में विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त क समुचित उपयोग पर जोर दिया गया है। उनके अनुसार 'सरकारों को जनता से संग्रहित धन का उपयोग न केवल नियमों, कानूनों व अधिनियमों के अनुरूप करना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकारी धन के व्यय में विश्वसनीयता, मितव्ययिता एवं बुद्धिमत्ता से काम ले तथा जनता से प्राप्त किये गए एक - एक रुपये का हिसाब-किताब रखे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामूहिक उत्तरदायित्व ही समन्वय स्थापित करने की शक्ति है। उनके अनुसार 'विभाजित उत्तरदायित्व, कार्यों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा आदि से कभी भी शासन की उत्तम व्यवस्था स्थापित में नहीं हो सकती एवं जहां शासन प्रणाली अच्छी नहीं है वहां वित्त व्यवस्था अच्छी होने की आशा नहीं की जा सकती है।' डॉ. भीमराव अंबेडकर के इस विचार के परिणामस्वरूप ही विभिन्न स्तरों की सरकारों (केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय ग्रामीण एवं शहरी निकाय) के बीच वित्त संसाधनों के विभाजन एवं वितरण पर सुझाव देने हेतु वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी।

**भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर विचार:** डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत में कृषि क्षेत्र की कई समस्याओं जैसे कृषि भूमि का असमान वितरण अर्थात् अधिकांश भूमि पर कुछ लोगों का अधिकार, छोटी जोतों की समस्या, कृषि कार्यों में अधिकांश आबादी का संलग्न होना आदि पर अपने विचार दिये। उनका कहना था कि भारत में कृषि क्षेत्र की इन समस्याओं के कारण

ही समुचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं जैसे कृषि भूमि के अनुपात में उत्पादन 3 में बढ़ोतरी, पर्याप्त आय एवं कृषि में संलग्न आबादी के जीवन स्तर में सुधार एवं वृद्धि आदि। डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार कृषि में उत्पादकता न मु केवल भूमि जोतों के आकार पर निर्भर है बल्कि अन्य कारकों जैसे श्रम, पूंजी एवं अन्य पूंजीगत आदानों से भी संबंधित है। अतः पर्याप्त मात्रा में श्रम एवं पूंजी की गुणवत्ता के साथ उपलब्धता भूमि की उत्पादकता को काफी बढ़ा सकती है। इसके अलावा यदि इन संसाधनों की पर्याप्तता के साथ कृषि मशीनों की उपलब्धता, छोटी जोतों वाली भूमि को भी उत्पादक बना देती है। हालांकि वे मानते थे कि कृषि में मशीनों का उपयोग छोटी जोतों की तुलना में बड़ी जोतों में अधिक सफल साबित रहती है।

**महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:** डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने आर्थिक विचारों में महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाएं सदियों से पुरुषों द्वारा उपेक्षित एवं विभिन्न सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास असंभव है इसलिए इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं स्तर सुझ करना आवश्यक है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार 'मैं प्रगति की उस डिग्री के द्वारा समुदाय की प्रगति को मापता हूँ जिसे महिलाओं ने प्राप्त किया है।' अतः उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला के आर्थिक स्तर को उपर उठाने एवं उन्हें देश की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है।

**श्रमिकों का उत्थान एवं कल्याण :** डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा कारखानों एवं मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण, इनके सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिये गए। उनके अनुसार औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए तथा वे ट्रेड यूनियनों के गठन एवं इनके अधिकारों एवं हितों के लिए आंदोलनों तथा पूंजीवाद के खिलाफ हड़तालों के समर्थक थे। इस प्रकार श्रमिकों के शोषण को रोकने तथा इनके आर्थिक कल्याण हेतु कार्य के घंटे, अवकाश, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संविधान में स्पष्ट निर्देश एवं अधिनियम का प्रावधान किया।

**कराधान नीति:** डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी के घोषणा पत्र में अपने आर्थिक विचारों के तहत कराधान संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए गए। उनके देश की किसी भी सरकार को अपनी कर व्यवस्था में जनता पर इस कर नहीं लगाने चाहिए जिससे समाज के गरीब एवं कमजोर लोग प्रभावित होते हों। करदाताओं को कर देने में सुविधाजनक लगे इसके लिए उन्होंने 'कराधान क्षमता' शब्द दिया जिसका अर्थ है कि उत्तम कर वह होता है जो कि लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुसार लगाया जाए।

**निष्कर्ष :** डॉ. भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता एवं दलित नेता होने के साथ एक ऐसे प्रबुद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक भेदभाव एवं विषमताओं को मिटाने के साथ आर्थिक विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण विचार दिए। डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो पाते हैं कि वे आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भविष्यवक्ता थे। उन्होंने उस समय देश में विभिन्न आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में जो आर्थिक विचार एवं सिद्धांत दिए वे वर्तमान दौर के विभिन्न आर्थिक मुद्दों एवं समस्याओं यथा कृषि, भूमि सुधार, श्रम सुधार, भारतीय मुद्रा, कराधान नीति, मुद्रा के मूल्यों में स्थिरता हेतु स्वर्ण प्रतिमान पर जोर, प्रांतीय वित्त विकास एवं विभिन्न स्तर की सरकारों में राजस्व के बंटवारे हेतु वित्त आयोग का गठन आदि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। इनको अपनाकर देश अपने आर्थिक सशक्तिकरण के साथ समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित कर सकता है।

## संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ambedkar B. R. (13 August 1921) Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India, University of London - Via Google book.
2. London School of Economics releases B. R. Ambedkar Achieves, DNA India, 2016.
3. Dr. B. R. Ambedkar :- As an Economist, International Journal of Humanities and Social Science Invention (www.ijhssi.org), Volum-2, Issue 3
4. Essay on Ambedkar Ideas - his Economic and Philosophical thoughts. ([www.sociologygroup.com](http://www.sociologygroup.com)),
5. Dr. B. R. Ambedkar and His Economic thought (www.academia.edu).
6. Rajendra Kumar Arya and Topan Choure - "The Economic thought of Dr. Bhimrao Ambedkar with respect of agriculture sector" Developing Country Studies, Vol. 4,
7. P. Abraham, "Notes on Ambedkar wates Resources Policy" Economic and Political weekly, Vol. 37, No 48, (Nov. 30, Dec. 6, 2002).
8. प्रबुद्ध अर्थशास्त्र :- अम्बेडकर और उनकी आर्थिक दृष्टि 'फॉरवर्ड प्रेस' (मासिक पत्रिका), फारवर्ड प्रेम, 803 / 92 नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली,
9. डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन- 'आखरमाला' ( समाचार पत्र)
10. मौर्य, राजेश एवं किरार, संजय : 'डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक- आर्थिक विचार'

